an>

Title: The Minister of External Affairs made a statement regarding her visit to Islamabad and recent developments relating to ties between India and Pakistan.

विदेश मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अफ़गानिस्तान से संबंधित 'हार्ट ऑफ एशिया' सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करने के लिए हाल ही में इस्लामाबाद गयी थी। उस यात्रा के दौरान भारत-पाकिस्तान संबंधों के विषय में हुए घटनाक्रम पर मैं इस पुनीत सदन और माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सम्मेलन 'हार्ट आफ एशिया' - इंस्ताबुल प्रक्रिया का पांचवां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन था, जो 8-9 दिसंबर, 2015 को इस्लामाबाद में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य सुरक्षा और संपर्क को बढ़ाना था। यह सम्मेलन अफ़गानिस्तान में स्थिरता तथा विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और उसके भविष्य के प्रति हमारी आस्था को पुनः दोहराने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना। 'हार्ट ऑफ एशिया' अफ़गानिस्तान पर राजनीतिक विचार विमर्श और क्षेत्रीय सहयोग की एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रक्रिया है। भारत ने 'हार्ट ऑफ एशिया' में प्रारम्भ से ही एक सक्रिय भूमिका निभायी है। इस सम्मेलन में अफ़गानिस्तान के निकटवर्ती तथा विस्तारित पड़ोसी मित्र राष्ट्र, उसका समर्थन करने वाले अन्य राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि इकट्ठे होते हैं और एक संगठित, लोकतांत्रिक, स्वतंत्र, मजबूत तथा प्रगतिशील अफ़गानिस्तान के लिए राजनीतिक विचार-विमर्श करते हैं और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हैं। इस्लामाबाद की मेरी इस यात्रा में भारत की अफ़गानिस्तान के प्रति इसी मजबूत प्रतिबद्धता को फिर दर्शाया गया। इस सम्मेलन में मैंने अपने वक्तव्य में अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान के रास्ते भारत तक पूर्ण एवं सीधे ट्रांजिट मार्ग खोलने का आग्रह किया। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों के परिपेक्ष्य में मैंने दक्षिण एशिया में शांति एवं विकास के लिए आत्मविश्वास और परिपक्वता के साथ मिलकर काम करने की पैरवी भी की।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह भी सूचित करना चाहूंगी कि इस्लामाबाद की अपनी इस यात्रा के दौरान मैंने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री श्री नवाज़ शरीफ से मुलाक़ात की और पाकिस्तान के अपने समकक्ष श्री सरताज अज़ीज़ के साथ भी विचार-विमर्श किया। इन बैठकों के उपरांत पाकिस्तान के साथ एक समग्र द्विपक्षीय वार्ता, यानी कंप्रीहैंन्सिव बायलैटरल डायलॉग शुरू करने के सरकार के निर्णय की घोषणा 9 दिसंबर, 2015 को इस्लामाबाद में एक संयुक्त वक्तव्य के माध्यम से की गयी। यह निर्णय दोनों देशों के बीच हाल ही के घटनाक्रमों और वार्ताओं, विशेषकर 6 दिसंबर, 2015 को बैंकॉक मे दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच हुई रचनात्मक बातचीत के उपरांत लिया गया। दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की ये बैठक, 30 नवंबर, 2015 को पेरिस में हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री श्री नवाज़ शरीफ के बीच हुई बातचीत के परिणामस्वरूप हुई थी।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन को विदित है, पाकिस्तान के प्रधान मंत्री श्री नवाज़ शरीफ को मई, 2014 में भारत में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में हमारे प्रधान मंत्री जी ने अन्य सार्क देशों के नेताओं के साथ आमंत्रित किया था। यह निमंत्रण पाकिस्तान के साथ अच्छे पड़ोसी संबंध रखने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता था। साथ ही यह दक्षिण एशिया में पारस्परिक एकता के माध्यम से इस क्षेत्र में शांति एवं विकास की हमारी सोच के अनुरूप था। प्रधान मंत्री श्री नवाज़ शरीफ की नई दिल्ली यात्रा के दौरान दोनों प्रधान मंत्रियों के बीच हुई इस प्रथम बैठक में हमने भारत-पाकिस्तान संबंधों पर अपने विचारों और आतंकवाद तथा हिंसा पर हमारी चिंताओं से पाकिस्तानी पक्ष को अवगत कराया, लेकिन दोनों पक्षों के बीच मई, 2014 मे लिए गए निर्णय के अनुरूप निर्धारित बैठकें नहीं हो सकीं।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन को विदित है कि भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों ने जुलाई, 2015 में ऊफा में मुलाकात की और इस बात पर सहमत हुए कि शांति सुनिश्चित करने और विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी दोनों देशों की है। उन्होंने सभी प्रकार के आतंकवाद की भर्त्सना की और दक्षिण एशिया में आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए एक-दूसरे के साथ सहयोग करने पर सहमति भी व्यक्त की। इसी उद्देश्य से दोनों देशों ने आतंकवाद से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया। दोनों ने यह भी इंगित किया कि दोनों देश सभी बकाया मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ऊफा सम्मेलन के दौरान प्रधान मंत्री श्री नवाज़ शरीफ ने हमारे प्रधान मंत्री जी को वर्ष 2016 में सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद आने के लिए आमंत्रित किया।

उपाध्यक्ष महोदय, ऊफा में प्रस्तावित दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और डी.जी.एम.ओ. की प्रस्तावित बैठकें नहीं हो सकीं, इसके कारण हम सभी को पता है। हालांकि, ऊफा में हुई सहमति के अनुसार सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच बैठक हुई और कई मानवीय पहलुओं को भी लागू किया गया। इस पृष्ठभूमि में जब हमारे प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज़ शरीफ के साथ 30 नवम्बर को पेरिस में COP-21 शिखर वार्ता के दौरान मिले तो इस बात पर चर्चा हुई कि दोनों देशों के बीच दोबारा किस तरह बातचीत का माहौल बनाया जा सकता है। इसके पीछे यह भावना थी कि हम दोनों पड़ोसी देशों के बीच लगातार दूरी हमारे क्षेत्र में शांति स्थापित करने तथा इसे एक प्रगतिशील क्षेत्र के रूप में विकसित करने के हमारे साझा सपने के मार्ग में एक अड़चन है। साथ ही यह भी बिलकुल स्पष्ट था कि हमारे बीच संबंधों को विकसित करने के मार्ग में मुख्य बाधाओं, विशेषकर आतंकवाद से प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट रूप से निपटने की भी आवश्यकता है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि यह सदन भी इस भावना से पूरी तरह सहमत होगा।

पेरिस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज़ शरीफ के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी की बातचीत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने निर्णय लिया कि दोबारा एन.एस.ए. स्तर की बातचीत शुरू की जाए। उसी के अनुसार दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 6 दिसम्बर, 2015 को बैंकॉक में मुलाकात की। दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच बातचीत स्पष्ट, सौहार्दपूर्ण तथा रचनात्मक माहौल में हुई। यह चर्चा शांति और सुरक्षा, आतंकवाद, नियंत्रण रेखा पर अमन-चैन तथा जम्मू और कश्मीर पर केंद्रित थी। जम्मू और कश्मीर वह राज्य है जो आतंकवाद और नियंत्रण रेखा के उल्लंघन से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है।

"हार्ट ऑफ एशिया" सम्मेलन के लिए मेरी इस्लामाबाद यात्रा सुरक्षा, आतंकवाद इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच सकारात्मक बातचीत के दो दिनों बाद हुई और इस्लामाबाद में मेरी प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ तथा श्री सरताज अज़ीज के साथ बैठकें इसी सकारात्मक प्रगति की पृष्ठभूमि में आयोजित की गई। दोनों पक्षों ने आतंकवाद की भर्त्सना की और इसे खत्म करने के लिए आपसी सहयोग करने का संकल्प लिया। साथ ही हमने मुम्बई आतंकी हमले से संबंधित न्यायिक कार्रवाई में पाकिस्तान द्वारा तेजी लाने की आवश्यकता पर बल दिया। पाकिस्तान द्वारा भारतीय पक्ष को इसे शीघ्र अंजाम तक पहुंचाने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में आश्वस्त किया गया।

इसी के अनुसार पाकिस्तान के साथ एक नए शीर्षक "समग्र द्विपक्षीय वार्ता" यानी "कंप्रिहेंसिव बायलेट्रल डायलोग" के अंतर्गत बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया गया। दोनों देशों के विदेश सचिवों को इस नई वार्ता की रूपरेखा और सारणी तय करने का कार्य सौंपा गया है।

मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगी कि यह सरकार देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इस संबंध में किसी भी प्रकार के खतरे से निबटने के लिए सरकार कूटनीतिक प्रयोगों सहित वे सभी कदम उठाएगी जो आवश्यक हों। साथ ही हमारी सरकार पाकिस्तान सहित अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण एवं सहयोगात्मक संबंधों के प्रति वचनबद्ध है ताकि दक्षिण एशिया में शांति और विकास के लिए जो प्रयास इस सरकार ने अपना कार्यभार संभालने के समय शुरू किए थे, उन्हें आगे बढ़ाया जा सके। पाकिस्तान के साथ इस नवीन वार्ता के दो उद्देश्य हैं - चिंता के विषयों पर रचनात्मक बातचीत के जरिए समस्याओं का निराकरण करना और साथ ही सहयोगात्मक संबंधों को स्थापित करना तथा इस दिशा में नए मार्ग तलाशना। व्यापार और संपर्क द्वारा, लोगों के बीच आपसी संपर्क द्वारा और मानवीय पक्षों पर नई पहलों के द्वारा समूचे क्षेत्र का कल्याण हो सकता है और इससे आपसी समझ और विश्वास भी बढ़ सकता है। हम यह आशा करते हैं कि इस नवीन वार्ता से हमारे समूचे क्षेत्र में शांति और विकास का एक नया अध्याय शुरू होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी इस नई पहल को पूरे सदन का समर्थन हासिल होगा। धन्यवाद।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, please allow me. ...(*Interruptions*)

SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): Sir, please. ...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: No, questions.

...(*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: Sir, please allow me. ...(*Interruptions*) I have given a notice on this issue. I will just ask a clarification. I know that under Rule 372 no questions can be asked at this stage.

HON. DEPUTY SPEAKER: Yes.

PROF. SAUGATA ROY: I just want to seek a very brief clarification.

HON. DEPUTY SPEAKER: No.

PROF. SAUGATA ROY: No questions. I will not ask any questions. It is a very important matter.

HON. DEPUTY SPEAKER: We can have a discussion on this issue.

PROF. SAUGATA ROY: I have been giving notices for the last seven days on this issue. Now, the Minister makes a *suo motu* statement. Kindly allow us to ask some clarifications. ...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Prof. Saugata Roy, please take your seat.

...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Already you have stated that as per Rule 372 one cannot put a question at this stage, but I am suggesting that you can give a notice and we can take up discussion under Rule 193 with regard to this issue. Hence, we can take up some detailed discussion on this issue if Members feel that this would be better.

...(*Interruptions*)

SHRI MOHAMMAD SALIM : Sir, please allow us as the Minister is here.

PROF. SAUGATA ROY: Sir, 5-6 days later she is giving a statement. ...(*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : सौगत बाबू, आप मेरी बात सुनिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी मानती हूं कि नियमों के तहत इसकी अनुमति नहीं है लेकिन यदि आप अनुमति दें तो मैं स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हूं। आप प्रश्न पूछें और मैं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं।

HON. DEPUTY SPEAKER: That is not the question. Do not put it on me.

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं अपनी ओर से कहना चाहती हूं कि मैं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अगर माननीय सदस्य सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं।

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Sir, in view of the readiness of the hon. Minister to respond, I have a suggestion to make. We cannot have a deviation from the rules. But at the same time we can allow half an hour's discussion and also response by the Minister.

PROF. SAUGATA ROY: Half an hour discussion cannot be taken up in response to a statement. It can be only with regard to a question.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: You cannot have both. You raise the issue, she will respond, let us close it in half an hour and move on to the Bills. Otherwise, you have to give a notice and then go for a discussion. Either way, we have no problem.

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री ने जो हाफ एन ऑवर डिस्कशन कहा है, शायद माननीय सदस्य उसे हाफ एन ऑवर का नोटिस समझ रहे हैं। मंत्री जी का कहना है कि क्लैरीफिकेशंस के लिए आधा घंटा रख लीजिए और आधे घंटे में इसे समाप्त कर लीजिए।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : मैं यही कहना चाहता था। That can be a solution, Sir.

HON. DEPUTY SPEAKER: In that case, we can take up discussion for half an hour.

PROF. SAUGATA ROY: Mr. Deputy Speaker, Sir, I am very grateful to you, the hon. External Affairs Minister and the Parliamentary Affairs Minister for allowing to seek a few clarifications on the very important statement.

The Minister visited Islamabad on 8th and 9th December. Why did it take her five days after that to come to Parliament? That too she came to Lok Sabha after laying a statement in Rajya Sabha at 11 o'clock. Why has Lok Sabha been kept in the dark on such an important matter?

The Minister has said that there was a talk of NSAs scheduled in September 2015, that was cancelled because the Pak people met the Hurriyat people. Now, what has happened between September and December that the Prime Minister, NSA, Foreign Minister again started talking with them? What has happened in this period? Have the border infiltrations reduced, have Pakistani intelligence activities reduced, or have the firing incidents on the border reduced that suddenly from September to December we have a flip-flop and the Government has started talking?

My next question is with regard to what NSAs talked. The Minister stated that the NSAs discussed everything including terrorism and Jammu and Kashmir. What is there to discuss about Jammu and Kashmir? It is an integral part of India. Why are you discussing Jammu and Kashmir again? That has been the position of India all along.

We dwelt on the need for Pakistan to expedite the Mumbai terrorist attacks trial. The country would be interested to know what Pakistan has assured. It happened in 2008 and we are in 2015. When will the trial be concluded in Pakistan?

Lastly, we also want good relations with Pakistan, but not at the cost of our territorial integrity, not when we are being shelled along the border, not when the Pakistani intelligence agencies are increasing their activities including the ISI.

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Hon. Deputy Speaker, Sir, I thank you for giving me the opportunity to seek a clarification on the statement made by the hon. Minister for External Affairs about her recent visit to Pakistan.

From the statement I am happy to note that hon. Minister met both the Prime Minister and the External Affairs Minister of Pakistan. After the discussion, in the Joint Statement made on 9-12-2015 it was stated that the Government took a decision to begin Comprehensive Bilateral Dialogue with Pakistan.

My question to the hon. Minister is whether the hon. Minister discussed the issue of continuous infiltration of Pakistanis into our territory in Jammu and Kashmir and other places; and if so, what are the concrete measures that the Government of India is taking to stop such infiltrations.

Secondly, I may know from the hon. Minister whether the hon. Minister would also visit other neighbouring countries to take such measures as are necessary to bring normalcy in our relations with those countries. The other question is will the same war footing efforts be made to bring safety to our Indian fishermen on the Tamil Nadu coast?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Respected Deputy-Speaker, Sir, it is really gratifying to hear the External Affairs Minister reading out a statement after a successful visit to Pakistan but as has been said and is being discussed in the media in India and also in Pakistan there has been a flip-flop of relationship between both the countries.

After the gruesome attack in Mumbai, we had stopped our relationship asking the Pakistan Government to take action against the perpetrators of terrorist activities in Mumbai. Repeatedly, Pakistan had said they were stateless actors, they were not from that State but we have been repeatedly saying that they have been trained in Pakistan; they have been provided all sorts of logistic support from Pakistan; and those people are also being protected by the establishment of Pakistan; what action has been taken?

In this statement at least I can understand a mere assurance has been given to us that action will be taken against them, one can presume as per the law that is prevalent in that country but are we not all aware that since last so many years what Pakistan has been saying but not keeping their word?

At one point of time, the then Head of Government or Head of State of Pakistan had come here, paid a visit to Agra and subsequently went back. This had happened after the Kargil war when our Prime Minister had gone there in a bus trip and extended a hand of friendship but we were stabbed in the back.

Today, with the present dispensation here in Delhi, with the NDA Government under the leadership of Shri Narendra Modi, two meetings have already taken place. First, the Prime Ministers of India and Pakistan met in Ufa in July, 2015 and the second meeting was in Paris during the Climate Change Summit on the 30th November. We were actually eager to know from the Prime Minister himself – of course, with the collective responsibility, the External Affairs Minister has come out and given us the narration – what happened in between. But we are yet to know what major development has taken place in between – before the Ufa meeting and after the Paris Summit – that we have become so confident that things can progress.

There are perpetrators of crime who have done grievous, heinous crime in this country, who were exported from Pakistan, who repeatedly shed blood on our borders. We would like to understand whether anything concrete has happened after that meeting that occurred in Bangkok.

श्री मोहम्मद सलीम: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंडम ने जो इनिसिएटिव लिया है, मैं तो पहले उसका स्वागत करता हूँ। हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध-सुधार के साथ-साथ आपने यह कहा कि जितने पड़ोसी देश हैं, उनसे अपने क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए अच्छे संबंधों की कोशिश करते रहेंगे। आपने यह भी कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि सदन भी आपके साथ होगा। इस क्षेत्र में स्टैबिलिटी हो, पीस हो, लोगों के बीच और पड़ोसी देशों के बीच में अच्छे संबंध हों, हम उसके पक्ष में हैं और इस बात के पक्षधर हैं।

हम यह भी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिलेशन्स में रोलर कोस्टर जैसा चलता है, यह मेटाफर ठीक नहीं है, रोलर कोस्टर जब नीचे आता है तो बहुत हंगामे के साथ तेजी से आता है और जब चढ़ाई होती है तो दिक्कत से होती है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि चढ़ाई बहुत खामोशी से ऊंचाई तक हो गयी और जब नीचे आता है तो मीडिया में युद्ध की घोषणा हो जाती है। हमारे यहां गुरुदासपुर में, उधमपुर में जब टेररिस्ट्स अटैक्स हुए, उससे पहले हुर्रियत वाला मामला भी आया, हम हमेशा यह कहते हैं कि हम बातचीत बन्द कर देंगे। यह इसी सरकार की बात नहीं है, पिछली सरकार में भी हमने देखा कि हम बातचीत बन्द कर देते हैं, जबकि हम यह समझते हैं कि हमारी हर समस्या गोली से नहीं, बोली से ही हल होगी और इसके लिए हमें वार्ता चलानी चाहिए, संवाद करना चाहिए। लेकिन हमारे देश की सुरक्षा का मामला अच्छे सम्बन्ध के साथ जुड़ा हुआ है।...(व्यवधान) अभी मुझे यह कहना है कि जब हम वार्ता बन्द करते हैं, जब भी कोई ऐसी घटना होती है, क्योंकि हमारे देश में और उस देश में भी ऐसे लोग हैं, जो हंगामे की सूरत पालना चाहते हैं, पनपने देना चाहते हैं, हो सकता है कि वहां ज्यादा हों, यहां कम हों, लेकिन हम हमेशा ऐसे बह जाते हैं।...(व्यवधान) आपने जो यह नई शुरूआत की है, तो पार्लियामेंट को यह एश्योर करना चाहिए कि जो नॉन-स्टेट एक्टर्स हों, स्टेट एक्टर्स हों या क्रॉस-बॉर्डर फायरिंग्स हों या एक्ट ऑफ टेरर हो, लेकिन आपने जो कप्रेहेंसिव डायलॉग शुरू की है,...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please conclude now.

SHRI MOHAMMAD SALIM: Sir, please allow me as it is an important issue. I am coming to the question. We have to put a very long lasting effort. यह

सब एक दिन में हल नहीं होने वाला है। हम बैंकाक में बैठक कर सकते हैं, हम पेरिस में और ऊफा में कर सकते हैं, लेकिन आपने जो मुद्दे खुद गिनाए हैं आखिरी पैराग्राफ में, मैं समय की कमी के कारण उनको रिपीट नहीं कर रहा हूं, इन तमाम मुद्दों को लेकर कप्रेंहेंसिव डायलॉग या पहले जो कम्पोजिट डायलॉग थी, उसको आप नए सिरे से शुरू कर रही हैं। ...(व्यवधान) मैं समझता हूं कि उसमें पाकिस्तान यह कहता है कि कश्मीर ही हमारा मुद्दा है और हम समझते हैं कि कश्मीर भी मुद्दा है, लेकिन अन्य मुद्दे जैसे पड़ोस का सम्पर्क, ट्रेड का मामला है।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: What is your question?

श्री मोहम्मद सलीम: सर, मेरा पहला प्रश्न यह है कि जब हमने पिछली बार वार्ता बन्द की और उसके बाद जब यह वार्ता शुरू की, क्या कांफिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुए? विश्व में कहीं भी डिप्लोमेसी में बैठक किसी थर्ड कंट्री में नहीं होती है, हमारा कांफ्रेंस की पहली शर्त यह होती है कि नई दिल्ली में हो या इस्लामाबाद में हो, फिर हमने बैंकाक में बैठक क्यों की? क्या हम इसे दिल्ली में नहीं कर सकते थे? यह एक समस्या रहेगी कि क्या इसे हम अपने तरीके से, अन्दरूनी तरीके से कर रहे हैं या किसी बाहरी दबाव से कर रहे हैं? हम इतनी तेज रफ्तार से कर रहे हैं, पन्द्रह दिन के अंदर, दस दिन के अंदर इतनी तेजी हुई। यही ठीक है कि बैंक में सब चलता रहता है, वह काम करना पड़ता है, लेकिन आपने जनता को साथ नहीं लिया।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Vinayak Raut, you put your question and do not give a speech.

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी श्रीमती सुषमा स्वराज जी का अभिनन्दन करता हूं कि भारत में शान्ति निर्माण हो,...(व्यवधान) इसके लिए उन्होंने जो प्रयास किए हैं, मुझे भरोसा है कि उसमें वह सफल हो जाएंगी, लेकिन एक शक है, खास करके भारत के साथ पाकिस्तान का जिस तरीके का रवैया पिछले कई वर्षों से रहा है- मुंह में राम, बगल में छुरी। ऐसा उनका बर्ताव रहा है। भविष्य में पाकिस्तान पर कितना भरोसा रखें और उनके ऊपर भरोसा रखने के बाद हिन्दुस्तान में पकिस्तान की तरफ से आतंकवादी कार्रवाई न हो, इसके लिए भारत को एलर्ट रहना पड़ेगा। जैसा अभी हेडली ने बताया है कि नसरत जहां एक सुसाइड बॉम्बर थी, उसने पूरा करके दिखाया है। भारत मे जब शान्ति निर्माण हो जाएगी, तब तक पाकिस्तान पर पूरी तरह से विश्वास न रखें और पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा जो कार्रवाई होती है, पूरी तरीके से उसका निपटारा करना चाहिए।

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, I thank you. On behalf of our Telugu Desam Party, we welcome the discussion that the Government has been having with their counterparts in Pakistan. I think it is very good to see that the stalemate has been broken as it had to happen at some point of time, earlier the better.

I want to know one thing from the Minister. Are we confident that Pakistan's long held policy of plausible deniability is ending or do they continue to follow the same path? If so, how do we get rid of the trust-deficit between the two countries?

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं सरकार को और विदेश मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और उन्हें धन्यवाद भी देता हूं उन्होंने भारत-पाक वार्ता शुरू की है। मैं इस बारे में कुछ स्पष्टीकरण चाहूंगा इसलिए मुझे थोड़ा अधिक समय दिया जाए, क्योंकि हमारा सूबा सरहद पर है। इसलिए पाकिस्तान बनने का सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब को झेलना पड़ा है। आज़ाद भारत में सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब को हुआ इसलिए मैं कुछ स्पष्टीकरण जानना चाहूंगा। मंत्री जी बताएं कि क्या वहां उनकी इस बात पर भी चर्चा हुई है कि समुद्री रास्ते से 300 से ज्यादा आइटम्स बाहर जाती हैं, लेकिन पंजाब की सीमा पर जो अटारी बॉर्डर है, वहां से 137 आइटम्स को ही क्यों रिस्ट्रिक्ट किया गया है? माननीय वाजपेयी साहब के समय भी पड़ौसी देशों के साथ दोस्ती हुई थी, आज भी हो रही है। मैं समझता हू कि सारा देश इसका स्वागत कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि उस समय जब वाजपेयी साहब ने समझौता किया था तो 671 मिलियन यू.एस. डालर्स का व्यापार बढ़ा था। अभी एक इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार तीन बिलियन यू.एस. डालर्स का सड़क के रास्ते व्यापार हो सकता है, लेकिन समुद्री लॉबी नहीं होने देती। क्या मंत्री जी ने इस पर भी कोई बातचीत की है? हमारे मंदिर और गुरुद्वारे साहिबान वहां पर हैं, उनकी सेवा-सम्भाल के लिए क्या मंत्री जी ने वहां की हुकूमत से कोई बातचीत की है? फैंसिंग के बाहर हमारी जमीन है, पाकिस्तान की हमारे इधर है, जैसे बांग्लादेश के साथ अभी सीमा के बारे में अहम् समझौता किया गया है, क्या वैसा समझौता पाकिस्तान के साथ भी किया जाएगा? गुरु नानक देव साहिब की कर्मभूमि करतारपुर साहिब, उसके लिए हम चाहते हैं कि आसानी से हमारा डेरा बाबा नानक से आवागमन हो। क्या मंत्री जी ने अपनी वार्ता में यह इश्यू भी उठाया है?

सुश्री महबूबा मुफ्ती (अनन्तनाग) : डिप्टी स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं वैलकम करना चाहती हूं विदेश मंत्री जी के पाकिस्तान जाने का। जैसा इन्होंने कहा कि जब भी हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बिगड़ते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू-कश्मीर का होता है। जम्मू-कश्मीर का ही नहीं होता है, बल्कि हर हफ्ते या हर महीने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज़ के गरीब लोग, चाहे सी.आर.पी.एफ. में हों, बी.एस.एफ. में हों या आर्मी में हों, जब उनकी वहां से लाशें यहां आती हैं, वह पूरे मुल्क का नुकसान होता है। हम यहां उन्हें श्रद्धांजलि देकर और टी.वी. पर डिबेट करके कह देते हैं कि बस हो गया, ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है कि विदेश मंत्री जी ने जो यह कदम उठाया है, यह बहुत सही है। वाजपेयी जी ने भी इस तरह की शुरूआत की थी। मुझे याद है जिस दिन वह लाहौर बस लेकर गए थे, उस दिन रात को कोटदारा में सात हिन्दू लड़कों को मार दिया गया, लेकिन वाजपेयी जी के कदम नहीं रुके। वाजपेयी जी के कार्यकाल में ही कारगिल का युद्ध हुआ, लेकिन तब भी उनके कदम नहीं रुके और उसके बावजूद उन्होंने मुशर्रफ साहब को बातचीत के लिए यहां बुलाया। संसद पर हमला हुआ, उसके बाद हमारा पाकिस्तान के साथ सीज़फायर हुआ। वाजपेयी जी समझते थे कि हमें अपना देश और अपना जम्मू-कश्मीर बचाना है इसलिए अगर हमें एक कदम ज्यादा चलना पड़े, तो कोई गलत बात नहीं है। जम्मू-कश्मीर की टेरीटोरियल की बात हमेशा होती है कि वह खराब नहीं होनी चाहिए। वहां जो बच्चे या औरतें रहती हैं, उनकी जिंदगी को भी ओन कीजिए, उसे अपनाइए, याती कश्मीर की जमीन आपकी नहीं है, जिसकी आप फिक्र करते हैं। जो लोग वहां दुख झेल रहे हैं, उनकी भी फिक्र कीजिए, जैसे वाजपेयी जी ने की थी। सन् 2000 से लेकर 2008 तक जो सीजफायर हुआ, बॉर्डर पर कोई गोली नहीं चली।

मुझे खुशी है कि सुषमा जी वहां गई और उन्होंने बात की। जैसे हमारे पंजाब के कुलीग वाघा बॉर्डर से हो रहे बिजनेस की बात कह रहे थे। मैं कहना चाहूंगी कि जब फायरिंग होती है, तब भी वहां से वाघा बॉर्डर पर प्याज़ आना बंद नहीं होता है। लेकिन जम्मू-कश्मीर में लोग अगर मर भी जाएं, तो भी वाघा बॉर्डर का बिजनेस नहीं रुकता है। क्रिकेट रुकता है, लेकिन बाघा बॉर्डर का बिजनेस नहीं रुकता है। वाजपेयी जी के समय में स्पेड वर्क हुआ था मुजफ्फराबाद रोड खुलने का, उसके बाद यू.पी.ए. सरकार में खुला। वहां भी आइटम्स पर रिस्ट्रक्शन है। दूसरा पाकिस्तान से हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं है। पाकिस्तान से आप जितने फोन कश्मीर करना चाहो, कर सकते हो, लेकिन यहां से वहां फोन नहीं कर सकते। इसके अलावा बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है। इन चीजों पर हम आगे नहीं बढ़ सके। मेरा विदेश मंत्री जी से यह जानना है कि क्या इन सबके बारे में भी कोई बात हुई है, ताकि हम जम्मू-सियालकोट या जो ऑलरेडी सड़क मार्ग खुले हैं, उससे ज्यादा कारोबार कर सकें, लोगों की आवाजाही ज्यादा हो, ताकि हमारे लोग देखें कि पर्दे के पीछे क्या है, वहां क्या है और हमारे यहां क्या है?

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, this is a clumsy climb-down but I welcome it. This is a procedural breakthrough but not a substantive breakthrough.

I would like to know from the hon. Minister on certain questions. Will this comprehensive bilateral dialogue be uninterruptible? Has the Government given an assurance that the Prime Minister will visit Islamabad during the SAARC Conference? Will India get the most favoured nation status? What steps have been taken to release the fishermen and exchange of prisoners? Will the Government relax the issues of visas? Whether the LoC trade or the old barter system would be finished? Will you agree with Sir Greek as maps are being drawn? For Siachen, will the Government be able to overrule its own Army? Is this Government really serious about Afghanistan? Afghanistan is going to be a grave challenge to us. After spending trillions of dollars, we still see that the Government is not in control. Are India and Pakistan going to sit down and talk about how stable Afghanistan can be made because it is in our interest that Afghanistan remains stable? Taliban is going to come back for sure over there. All experts

are saying this. These are not my words. So, what steps are taken in that regard? These are my specific pointed questions to the hon. Minister.

SHRI MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY (NELLORE): Sir, I welcome this move by the Government of India. Sir, definitely, we have to have peace with neighboring countries. As our former Prime Minister, Shri Atal Behari Vajpayee said, we can change our friends but we cannot change our neighbours. So, we have to have peace with our neighbouring countries. But I would like to know from the hon. Minister as to whether the Government of India, without compromising our territorial integrity, is going to have any negotiation with Pakistan or not?

डॉ. अरुण कुमार (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की इस पहल का स्वागत करता हूं। लेकिन मैं एक बात अवश्य जानना चाहूंगा कि इस देश ने बहुत कुछ खोया है और पाकिस्तान की हरकत में कोई तब्दीली नहीं आयी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ओक्योपाइड कश्मीर जो कि टेरेरिज्म की नर्सरी है, उस पर सरकार ने सख्त तरीके से अपना पक्ष रखा है या नहीं?

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Sir, I welcome the dialogues which have been opened with Pakistan. But we have been continuously seeing that on the one side, dialogues start and on the other side, Pakistan starts attacking us. This has always been happening. Can the Minister for External Affairs, when she had visited that country and had a dialogue with them, tell the House whether she got an assurance from that country or the leaders of that country that they are going to stop such activities? Even in my constituency, Mahabubnagar, I have seen many CRP soldiers being shot dead there and their dead bodies being brought there. Every fortnight, there is a cross fire from there. Keeping all these in view, how can we really have peace with them? This has to be determined. Now also, I have a doubt that on the one hand, our Minister for External Affairs had gone to Pakistan and had a dialogue with them but on the other hand, what planning is going on there? Our country has to be alert on that issue and not be at ease thinking that our Minister for External Affairs had gone there and everything will be all right. I have my doubt in that aspect. So, some action has to be rally taken and security should be enhanced.

PROF. SUGATA BOSE (JADAVPUR): We would like to congratulate our Minister for External Affairs for representing our country with great dignity at the Multi Lateral Meeting and also at the Bilateral Meeting with Pakistan.

I have a very specific clarification to ask. In the Statement that she has given to the House, the Minister for External Affairs had expressed her hope that in times to come, Pakistan will allow us transit to Afghanistan. Now, we know that, eversince the Chinese President visit in April, 2015, there have been discussions of a road that the Chinese will build through Pakistan.

At first, it was suggested that it would be a western road, through the Khyber Pakhtunkhwa province and Balochistan. But we later heard that there would also be an eastern alignment through Punjab up to Lahore.

Has the Minister of External Affairs raised this matter or has she given instructions to the Foreign Secretary to raise this matter with Pakistan so that our vital interests are protected?

We support you, of course, because we realize that we have to solve our problems with our neighbours in order to realize our legitimate ambitions to play a bigger role on the global stage. Thank you.

विदेश मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि आधे घंटे के समय में ही मेरे 13 सांसद साथियों ने अपने-अपने क्वैरिफिकेशंस और स्पष्टीकरण रखे हैं, जिनका उत्तर मैं देना चाहूंगी। सौगत दा ने क्वैरिफिकेशन शुरू करते हुए बहुत बुनियादी सवाल उठाया कि 9 तारीख को रात को मैं यहां आ गई थी तो मैं पांच दिन तक यहां स्टेटमेंट लेकर क्यों नहीं आई? उपाध्यक्ष महोदय, मैं रिकॉर्ड स्टेट करना चाहूंगी कि मैं 9 तारीख को रात को 12 बजे पहुंची थी, मैंने 10 तारीख को आ कर कहा कि मैं 11 तारीख को स्टेटमेंट देना चाहती हूँ। शुक्रवार को स्टेटमेंट के लिए मैं नोटिस देने आई थी। लेकिन राज्य सभा की बी.ए.सी. की हुई और उसमें उन्होंने यह कहा कि हमारे यहां क्वैरिफिकेशंस का प्रावधान है, और हम सेम डे क्वैरिफिकेशन चाहते हैं। उस दिन शुक्रवार था और क्योंकि आधा दिन ही होता है, 11 से 12 बजे तक वहां ज़ीरो ऑवर होता है और 12 से 01 बजे तक वहां क्वेश्चन ऑवर होता है, उसके बाद उन्होंने कहा कि बाद में हाफ डे होता है, क्यों प्राइवेट मैंबर्स बिल शुरू हो जाता है तो हम चाहेंगे कि विदेश मंत्री सोमवार को ही स्टेटमेंट दें। ...(व्यवधान) मेरे लिए दोनों सदन बराबर का महत्व रखते हैं, कोई लोक सभा कमज़ोर है या राज्य सभा ऊपर है, या लोक सभा नीचे है, राज्य सभा ऊपर है ऐसा नहीं है। यह बात वहां कह गई और मुझसे स्पेशली सचिवालय ने यह कहा कि आप सोमवार को स्टेटमेंट दीजिए। जब सोमवार की बात आई तो कहा गया कि राज्य सभा में 11 बजे ही ज़ीरो ऑवर शुरू हो जाता है, आप 11 बजे ही स्टेटमेंट दे दीजिए। अब 11 बजे स्टेटमेंट होगा और उसके बाद क्वैरिफिकेशन होने हैं, तो मैं यहां दो बजे ही आ सकी थी। इसीलिए मैंने दो बजे का समय रखा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि मैं कुछ छुपाना चाहती थी। मैं तो 10 तारीख को स्टेटमेंट तैयार कर चुकी थी, 11 तारीख को नोटिस देने आई थी। 11 तारीख को मैं यहां नोटिस देना चाहती थी, और चाहती थी कि शुक्रवार को ही यह मामला दोनों सदनों में निबट जाए। लेकिन जब मुझे यह कहा गया कि आप सोमवार को स्टेटमेंट दीजिए, तब मैंने सोमवार को दिया। इसमें कुछ छुपाने लायक नहीं था, जिसके लिए मैं स्वयं और तीन दिन मांगती।

दूसरी बात उन्होंने कही कि इस बीच में क्या बदला? ग्राउंड पर कुछ नहीं बदला। लेकिन सितंबर में जब यह तय हुआ था कि ऊफा में, ऊफा के बाद एनएसए की मीटिंग होगी, वह मीटिंग नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, वह भी आप जानते हैं। वह मीटिंग नहीं हो पाई और चूंकि हम लोग कहते थे कि terror and talks cannot go together. ऊफा में यह तय हुआ था कि let us first address the terror. अगर terror and talks cannot go together तो आइए पहले आतंकवाद पर ही बात करें। आतंकवाद पर कौन बात करे तो आतंकवाद पर एनएसए बात करें। लेकिन जो मीटिंग दिल्ली में होनी थी, वह यहां पर नहीं हो पाई, इसलिए यह बात आगे बढ़ी। फिर पैरिस में दोबारा मिले, तब उन्होंने कहा कि ऊफा में जो सहमति बनी वह आगे नहीं बढ़ पाई तो क्या अब

दोबारा बातचीत का माहौल बनाएं? बनाओ, कैसे बनाओ कि वह एनएसए लैवल टॉक्स पड़ी हैं अभी, वह होनी ज़रूरी हैं। तब यह हुआ कि एनएसए टॉक्स पहले हो जाएं। अगर नौ तारीख को मुझे जाना है तो छह तारीख को वे टॉक्स हो जाएं तो इसलिए ग्राउंड पर कुछ नहीं बदला। लेकिन जो चीज़ तय हुई थी कि पहले एनएसए लैवल टॉक्स होंगी, उसके बाद डायलॉग की बात होगी, वह एनएसए लैवल टॉक्स मेरे इस्लामाबाद जाने से दो दिन पहले हुई, इसलिए हमारी बातचीत बाद में इस्लामाबाद में हुई है।

तीसरा, आपने कहा कि मैंने कहा है कि जम्मू कश्मीर पर भी चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर पर चर्चा करने की क्या जरूरत थी, वह तो हमारा अटूट अंग है। तो मैं बता दूँ कि आप एक साथ सैंटेंस को पढ़िए कि सैंटेंस क्या है। मैं अंग्रेज़ी में पढ़ रही हूँ क्योंकि आपके पास वही है। The meeting was held in Bangkok. Discussions between the two NSAs in that meeting were held in a candid, cordial and constructive atmosphere. They focused on peace and security, terrorism, tranquility along the Line of Control and Jammu and Kashmir. आगे देखिए, सिर्फ हाइफन है, the State which has been most directly impacted by terrorism and violation of LOC.उपाध्यक्ष जी, जम्मू कश्मीर के आतंकवाद पर बात हुई। जम्मू कश्मीर में एलओसी के वॉयलेशन पर बात हुई। क्यों हुई यह भी बता देती हूँ। क्योंकि बात एनएसए लैवल की थी।

एनएसए लेवल में कभी मैन्डेट यह नहीं था कि आप जम्मू-कश्मीर के पॉलिटिकल स्टेट्स पर बात कर सकते हैं। अगर आप ऊफा का स्टेटमेंट पढ़ें तो उसमें बहुत साफ है, "NSAs will talk on all issues related to terrorism." अब चूँकि टैरिज्म से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य जम्मू-कश्मीर है, इसलिए जम्मू-कश्मीर के आतंकवाद पर भी चर्चा हुई, पॉलिटिकल स्टेट्स पर चर्चा नहीं हुई। आपके तीन सवाल थे, तीनों का जवाब मैंने दे दिया। वेणुगोपाल जी ने बात को थोड़ा डिफरेंट करके कहा। वेणुगोपाल जी ने कहा कि क्या मैं बाकी नेबरिंग कंट्रीज में भी जाऊंगी? मैं उनकी चिंता समझती हूँ, क्योंकि श्रीलंकन तमिल्स के बारे में और हमारे लोग, जो श्रीलंकन नेवी द्वारा, फिशरमैन जो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, उसके बारे में उनकी चिंता है। लेकिन मैंने इसमें ही लिखा है कि केवल पाकिस्तान नहीं, हमारे पूरे क्षेत्र के सहयोग के लिए मैं बात करूंगी। केवल उसके लिए हम बात नहीं करेंगे, श्रीलंका मैं स्वयं गई। श्रीलंका के विदेश मंत्री बनने के एक हफ्ते के भीतर वे भारत आए, उनके राष्ट्रपति आए और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री वहाँ गए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हर तरह की बातचीत में, हर स्तर की बातचीत में हमने दोनों मुद्दे श्रीलंकन तमिल्स का हित और हमारे फिशरमैन, जो हमारे मछुआरे पकड़े जाते हैं, उनके बारे में बात की। मैं बिल्कुल विजिट करूंगी। मेरा तो जेसीएम अभी श्रीलंका से तैयार पड़ा है, उसके लिए मैं श्रीलंका जाऊंगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। श्रीलंका के साथ भी हम अपने हितों की बात करेंगे।

तीसरे वक्ता हमारे श्री भर्तृहरि महताब जी थे। मैं दो बातों का जवाब देना चाहूँगी, जो उन्होने कहीं। एक तो उन्होंने कहा कि जैसे मीडिया कह रहा है फ्लिप फ्लॉप, भर्तृहरि जी मैं कहना चाहती हूं कि फ्लिप फ्लॉप का मतलब अगर यह है कि बातचीत शुरू होती है, रूक जाती है, फिर शुरू होती है, फिर रूक जाती है तो यह सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि बातचीत का शुरू होना, रूकना या फिर शुरू होना, यह कूटनीति का हिस्सा है। इसलिए यह डॉयलाग बहुत बार चला है और बहुत बार रूका है। आपने कहा कि मुंबई के हमले के बाद से यह रूका पड़ा था। यह मुंबई हमले के बाद से रूका नहीं पड़ा था। मुंबई हमला वर्ष 2008 में हुआ था। उसके बाद वर्ष 2010 में थिम्पू में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और उनके प्रधानमंत्री के बीच मीटिंग हुई थी और वहाँ यह डॉयलाग फिर से शुरू हो गया था और तब इसका नाम resumed dialogue था। यह तब से रूका नहीं पड़ा था। यह वर्ष 2011 में आकर रूका, जब सरबजीत सिंह की हत्या पाकिस्तान जेल में हुई और सलाउद्दीन की हत्या भारत की जेल में हुई। इसलिए यह फ्लिप फ्लॉप नहीं है, यह कूटनीति का एक हिस्सा है। इसलिए हम इसे फ्लिप फ्लॉप न कहें। जहाँ तक आपका यह कहना है, आपने मुझे बधाई दी, मुझे एक चीज की खुशी है कि सारी की सारी बात में ओवैसी जैसे भाइयों ने थोड़ा सा राइडर लगा दिया clumsy climb down कहकर, लेकिन ओवरऑल सबने इसका स्वागत किया है, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, लेकिन भर्तृहरि जी, यह फ्लिप फ्लॉप नहीं है, यह मैं आपसे कहना चाहूँगी।

मोहम्मद सलीम जी ने भी स्वागत किया है, बल्कि उन्होंने तो सीधे-सीधे कहा कि मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन आपका एक प्रश्न आया। मैं वह-वह प्रश्न ले रही हूँ, जो दोहराए नहीं गए हैं। आपने कहा कि बैंकाक में हुआ, थर्ड पार्टी कंट्री हो गया। बैंकाक अगर थर्ड पार्टी कंट्री हो गया तो फिर ऊफा में जो बात हुई तो रूस भी पार्टी हो गया। पेरिस में बात हुई तो फ्रॉंस भी पार्टी हो गया। न्यूयार्क में यह बात होने वाली थी तो अमेरिका भी पार्टी हुआ।...(व्यवधान) यहाँ तो साइड लाइन्स भी नहीं थी। मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि थर्ड पार्टी तब होता है, जब दो देशों के अलावा कोई तीसरा देश बातचीत में बैठता है।...(व्यवधान)

सलीम साहब, एक मिनट आप मेरी बात सुनिए। थर्ड कंट्री पार्टिसिपेशन यह देखकर होगा कि बातचीत में कौन-कौन बैठा, यह देखकर नहीं होगा कि बातचीत कहाँ हुई? बातचीत तो कहीं न कहीं पृथ्वी पर होगी ही, केवल दिल्ली और इस्लामाबाद में नहीं। जैसा मैंने कहा, डॉयलाग की शुरूआत की बात थिम्पू में हुई तो भूटान पार्टी हो गया। एक बार हवाना में हुई, मुशर्रफ साहब के साथ तो क्यूबा पार्टी हो गया। इसलिए मेरा यह कहना है कि थर्ड पार्टी कंट्री का पार्टिसिपेशन यह देखकर माना जाएगा कि क्या उस देश को हम लोगों ने मध्यस्थता स्वीकार करके बातचीत मे बिठाया। कौन बैठा, इस पर थर्ड कंट्री आएगा, कहाँ बातचीत हुई, इस पर थर्ड कंट्री नहीं आएगा। इसलिए यह कहना कि बैंकाक में बातचीत हुई तो थर्ड कंट्री आया और यह जो आपने कहा कि तुरन्त ऊँचाई आ गई, यह इसीलिए आ गई कि मीडिया हाइप हो ही नहीं पाया। दिल्ली और इस्लामाबाद में जब बातचीत होती है तो कितना हाइप आता है, लेकिन बातचीत बैंकाक में हुई और कोई मीडिया से छिपकर नहीं हुई। हम लोगों ने कहा, उसके बाद भी स्टेटमेंट निकला कि बातचीत बहुत अच्छे वातावरण में हुई। गुपचुप कुछ नहीं हुआ।

15.00 hours

लेकिन महज़ बैंकाक में हो जाने के कारण वह थर्ड पार्टी कंट्री बन गया तो ऐसा नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि यह कह देना कि बैंकाक में बात हुई, इसलिए थर्ड कंट्री आ गया, यह नहीं है। बाकी जो आपका कहना है कि एक आश्वासन दो कि अनइंटरप्टेबल डॉयलॉग होगा, ऐसा कभी होता नहीं है। हम लोग यह चाहेंगे कि जो सबोटियर, जिनकी आपने चर्चा की, जो डॉयलॉग को किसी न किसी तरह से रोकना चाहते हैं, उनसे प्रोवोक न हों और डॉयलॉग से ही रास्ता निकलेगा और इसलिए इस डॉयलॉग से रास्ता निकालें, यही हमारा मत इसमें रहेगा।

चन्दूमाजरा जी ने बात की और आपने हमसे पूछा कि क्या आपने इस पर बात की है, समुद्र के रास्ते से व्यापार हो, क्या आपने इस पर बात की है कि हमारे जो गुरुद्वारे हैं, उनकी सेवा हो। एक-एक बात वहां अलग-अलग नहीं हुई, चन्दूमाजरा जी। लेकिन मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी है कि हम लोगों ने जो पिलर्स टॉक्स के बनाये, जो पुराने कम्पोजिट डॉयलॉग में भी चले आ रहे हैं, उसमें हमने नये सिरे से रिलीजियस टूरिज्म डाला है और रिलीजियस टूरिज्म डालने का मतलब है, जो गुरूद्वारों की सेवाएं हैं, वे भी, हम उसमें कटासराज की बात भी करते हैं। हम उनके यहां आने पर अजमेर शरीफ साहब और निजामुद्दीन औलिया आने की भी बात करते हैं तो रिलीजियस टूरिज्म में यह बात आएगी।

इसी के साथ मैं महबूबा जी का जवाब दे दूं कि आपने भी पूछा कि क्या यह बात हुई कि वाघा अटारी बोर्डर पर हमारा व्यापार बढ़ेगा। यह जो पिलर्स हैं, उसमें ट्रेड एंड ट्रांजिट एक बहुत बड़ा पिलर है और ट्रेड एंड ट्रांजिट में ये दोनों चीजें आएंगी। वाघा अटारी बोर्डर भी आएगा, कनैक्टिविटी भी आएगी। वे सारी की सारी चीजें इसमें आएंगी तो जो पिलर्स हमारे हैं, जिसमें ओवेसी जी ने तो 4-5 पिलर्स गिना दिये, मैं कहना चाहूंगा, ओवेसी साहब, इसमें सरक्रीक भी है, इसमें सियाचिन भी है, इसमें वुल्लारबराज भी है, इसमें तुलबुल नेवीगेशन प्रोजैक्ट भी है तो ये सारी की सारी बातें, जितनी आपने पूछीं, वे सारी की सारी इसमें हैं। ट्रेड एण्ड ट्रांजिट भी है, जो महबूबा जी चाह रही हैं और चन्दूमाजरा जी, जो आप चाह रहे हैं, रिलीजियस टूरिज्म भी इसमें है। वहां यह बात नहीं हुई, वहां यह बात हुई कि दोनों जगह के विदेश सचिव बैठ करके एक सारणी बना लें, उसमें ये पिलर्स हैं और किस किस स्तर पर बात होगी, यह भी तय है।

अन्त में, यह भी मैं आपको बता दूं कि टैरिज्म का भी हमने लेवल बढ़ा दिया है। अब टैरिज्म की जो टॉक होगी, वह एन.एस.ए. लेवल पर हुआ करेगी। टैरिज्म का स्तर एन.एस.ए. लेवल का होगा, बाकी जो सैक्रेटरीज़ के स्तर का होगा, जो अगली विदेश सचिव की वार्ता है, उन तीनों वार्ताओं में वार्ता के अन्दर ये सारे पिलर्स तय कर दिये जाएंगे। बाकी ज्यादातर साथियों ने चाहा है, चाहे वे विनायक जी हों, चाहे वे जयदेव जी हों, चाहे वें जितेन्दर रेड्डी हों, चाहे वे राजामोहन रेड्डी हों, इन सब के, चारों के सवाल ट्रस्ट पर सम्बन्धित थे कि ऐसा क्या हो गया या आगे ऐसा सुनिश्चित होगा क्या? मैं एक ही बात कहना चाहती हूं कि बातचीत जब भी होती है, भरोसा करके ही होती है और मैं एक और आपको बता दूं कि जब हमने यह तय कर लिया कि तीसरे देश की मध्यस्तता हम स्वीकार नहीं करेंगे, तीसरी पार्टी की मध्यस्तता स्वीकार नहीं करेंगे, तीसरे व्यक्ति की मध्यस्तता स्वीकार नहीं करेंगे तो बातचीत तो दोनों देशों को ही करनी होगी। अगर किसी तीसरे की मध्यस्तता स्वीकार नहीं तो बातचीत तो दोनों देशों को ही करनी होगी। इसीलिए जो मैंने इसमें एक जगह पढ़ा कि जो हमारे रिश्ते पूरे क्षेत्र में खराब हो रहे हैं, वे हमारे दोनों देशों की लगातार दूरी के कारण हो रहे हैं। सार्क उस तरह से टेक ऑफ नहीं कर पा रहा, जिस तरह से बाकी दूसरी ग्रुपिंग्स कर गईं। इसलिए इस दूरी को पाटना बहुत जरूरी है और मुझे यह खुशी है कि हमने यह काम सरकार में आने के बाद नहीं, प्रधानमंत्री जी ने शपथ लेने के बाद नहीं, शपथ लेने से पहले सार्क के तमाम के तमाम नेताओं को यहां बुलाया, नवाज शरीफ साहब को भी बुलाया। यह बातचीत उस समय से शुरू हुई, यह बातचीत ऊफा से शुरू नहीं हुई। मैं तो उस वार्ता की साक्षी हूं। 26 मई को हमारा शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें नवाज साहब आये। सारे नेता आये। एक बंगलादेश का रिप्रेजेण्टेशन स्पीकर के लेवल पर हुआ, क्योंकि उनकी प्राइम मिनिस्टर उस समय जापान गई हुई थीं। वे नहीं आ सकी थीं, बाकी सब के सब लोग आये। नवाज साहब भी आये। अगले दिन बाइलेटरल

मीटिंग सब के साथ हुई। वहीं यह तय हुआ कि जब नवाज साहब ने कहा, फॉरेन सैक्रेटरी लेवल टॉक शुरू करो तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बिल्कुल करो। लेकिन आप भी वाघा और अटारी बोर्डर पर व्यापार शुरू करिये। अब यह अलग बात है कि एफ.एस. लेवल टॉक्स के चार दिन पहले वह वार्ता रद्द करनी पड़ी, मैं उन कारणों में जाना नहीं चाहती, वे सारे कारण आप लोग जानते हैं। लेकिन जिस समय अभी वे पी.एम. डेजिग्नेट थे, हमारी पार्टी ने और एन.डी.ए. ने मिलकर उनको नेता चुना था, अभी उन्होंने शपथ भी नहीं ली थी, यह सम्बन्ध सुधारने का काम उन्होंने तब से शुरू कर दिया था और सारे सार्क नेताओं को निमत्रण दिया था। उसी चीज़ को उन्होंने ऊफा में आगे बढ़ाया। जब सार्क सम्मेलन के दौरान की हुई हमारी बातचीत पूरी नहीं हो पाई तो उसी को उफा में बढ़ाया। जब उफा वाली बातचीत पूरी नहीं हुई, तो फिर उसे पेरिस में बढ़ाया, यानि जब-जब उन दोनों की मुलाकात हुई है, तो जिन-जिन चीज़ों पर सहमति हुई थी, मगर वह नहीं हो पायी तो उन्होंने वहीं से उसका सूत्र पकड़ा और उसे आगे ले गए। पेरिस में जब उन्होंने उसका सूत्र पकड़ा और बैंकॉक में मीटिंग हो गयी तो आप मुझे बताइए कि एन.एस.ए. लेवल की मीटिंग होने के बाद अगला रोडमैप क्या होता है और क्या होना चाहिए था? अगर यहां एन.एस.ए. लेवल की टॉक्स हो जाती, तो आप भी और हमारा मीडिया भी, मुझसे यही सवाल पूछता कि अब कॉम्पोज़िट डॉयलोग कब शुरू कर रहे हैं? यही एक कारण है कि इसका सब ने स्वागत किया। हर एक ने इसका स्वागत किया। एक ने भी आलोचना नहीं की। कुछ ने आशंकाएं जरूर प्रकट की हैं और वह अतीत के कारण से। पीछे जो होता रहा, उसके कारण आशंकाएं प्रकट की गयीं। लेकिन, जैसा मैंने कहा कि भरोसा करके ही बातचीत शुरू होगी, जब भी बातचीत शुरू होगी।

अब आलोचना करने वाले तो अजीब-अजीब आलोचना करते हैं। साड़ी का रंग हरा क्यों था? उर्दू में क्यों बोलीं?...(व्यवधान) अरे भई, मैं बुधवार को हरी साड़ी ही पहनती हूं और उस दिन बुधवार था और मैंने हरी साड़ी पहनी थी।...(व्यवधान) हमारे यहां से किसी ने इसके बारे में नहीं बोला।...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : सुषमा जी, आपकी उर्दू नवाज़ शरीफ से अच्छी थी।...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : सौगत दा, इस बात की भी आलोचना हुई कि मैंने वहां उर्दू क्यों बोली? मैं उन आलोचना करने वाले लोगों को कहना चाहूंगी कि उर्दू मेरे मुल्क़ की भी ज़ुबां है। उर्दू केवल उनकी ज़ुबां नहीं है, उर्दू मेरे मुल्क़ की भी ज़ुबां है। अगर मैं बैंकॉक में विश्व संस्कृत सम्मेलन में जाकर संस्कृत में भाषण देती हूं, तो जब मैं उर्दू में पाक़ मीडिया से रू-ब-रू होती हूं, तो उनसे मुख़ातिब होते हुए मैं उर्दू क्यों नहीं बोलूंगी? यह मेरे मुल्क़ की भी ज़ुबान है। इसलिए मैंने वहां उर्दू में बात की।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please don't divert.

श्रीमती सुषमा स्वराज : मरियम के साथ मेरी क्या बात हुई? मरियम तो उनकी बेटी हैं। मेरी उनकी वालिदा से भी बात हुई। वह भी वहां थीं। मैं वहां नवाज़ साहब की चार पीढ़ियों से मिली। नवाज़ साहब की वालिदा यानी उनकी मदर, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, और बेटी के भी आगे दो बेटियां - मैं उनकी चार पीढ़ियों से एक साथ मिली, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में ये चीज़ें अहमियत रखती हैं, महत्व रखती हैं।

इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि बहुत ही अच्छे माहौल में यह बातचीत शुरू हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच अगर संबंध अच्छे होते हैं, तो फिर पूरे क्षेत्र में भी शांति बढ़ने की बात आगे आती है और शांति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। मुझे लगता है कि, जो मैंने अन्त में कहा था, कि मुझे सदन का समर्थन हासिल होगा, तो मुझे इस बात की खुशी है कि इस आधे घंटे की चर्चा ने यह पुष्ट कर दिया कि पूरे सदन का समर्थन इस इनिशिएटिव को मिल रहा है, इस पहल को मिल रहा है। इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया भी अदा करती हूं, आभार भी व्यक्त करती हूं।

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Sugata Bose, I allowed you as a special case. Please don't quote this in future as one more person from the same party has been allowed.

-

15.08 hours

MATTERS UNDER RULE 377 *

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, the matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over the text of the matter at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.